के. श्रीकांत सिंह

बनाम

मैसर्स नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटीज लिमिटेड और अन्य

20 जुलाई, 2007

[एस. बी. सिन्हा और एच.एस. बेदी, जे. जे.]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881: धारा 138 और 141:

अधिनियम की धारा 138 का अपराध करने के लिए किसी कंपनी और उसके निदेशकों के विरुद्ध परिवाद निदेशकों में से एक द्वारा सी.आर.पी.सी. की धारा 482 के तहत कार्यवाही निरस्त करने हेतु याचिका दायर उच्च न्यायालय द्वारा खारिज अपील पर अभिनिर्धारित कियाः कंपनी के निदेशक के प्रत्यावर्ती दायित्व को दिखाने के लिए, परिवादकर्ता पर यह अभिवचन करना अनिवार्य है कि अभियुक्त कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था - परिवादकर्ता द्वारा ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है केवल इसलिए कि अभियुक्त-निदेशक ने परिवादकर्ता से वित प्राप्त करने के लिए बातचीत में भाग लिया था. यह नहीं कहा जा सकता है कि यह कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों के लिए जिम्मेदार था इसके अलावा, अभियुक्त के खिलाफ प्रत्यावर्ती दायित्व का अनुरोध किया जाना चाहिए और उसे साबित किया जाना चाहिए। यह केवल अनुमान का विषय नहीं हो सकता है इन परिस्थितियों में, आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं

रखा जा सकता है, इस प्रकार, रद्द किया जाता है और परिवाद का संज्ञान लेने वाले आदेश को निरस्त किया गया दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 482.

इस अपील में निर्धारण हेतु प्रश्न यह उठा कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थी, अभियुक्त कंपनी के निदेशक को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अपराध करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

अपीलार्थी निदेशक ने तर्क दिया कि प्रासंगिक समय पर वह कंपनी का निदेशक नहीं थे और यह कि परिवाद याचिका में लगाए गए आरोपों के आधार पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 के प्रावधानों की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1. किसी कंपनी के निदेशक के प्रत्यावर्ती दायित्व को दिखाने के लिए, परिवाद पर यह अभिवचन करना अनिवार्य है कि अभियुक्त कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था। परिवाद याचिका में ऐसा कोई आरोप नहीं लगाए जाने के कारण, उच्च न्यायालय आक्षेपित निर्णय पारित करने में सही नहीं था। [पैरा 4] [455-डी. ई]

1.2. आरोप है कि सभी अभियुक्त निदेशकों ने भाग लिया अभियुक्त नंबर 1 के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बातचीत से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि अपीलार्थी कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों के लिए जिम्मेदार था। [पैरा 4] [455 ई. एफ]

एस. एम. एस. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला और अन्य [2005] 8 एससी 89 पर भरोसा किया।

1.3 कंपनी की ओर से उसके निदेशकों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बातचीत, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध गठित करने के उद्देश्य से एक घटक नहीं है। इसके अलावा, एक व्यक्ति की ओर से एक प्रत्यावर्ती दायित्व का अनुरोध किया जाना चाहिए और उसे साबित किया जाना चाहिए। यह केवल अनुमान का विषय नहीं हो सकता है। [पैरा 5] [456-ई]

सबिता राममूर्ति और अन्य बनाम आर. एस. एस. चन्नबसवराध्या. मे. [2006] 10 एससीसी 581 पर भरोसा किया।

2. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार इसे रद्द किया जाता है। संज्ञान लेने का आदेश निरस्त किया जाता है। [पैरा 7] [457-एफ]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 919/2007

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय हैदराबाद के आपराधिक याचिका संख्या 4084 / 2006 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 12.09.2006 से।

अनिल कुमार तांडले अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

एस. बी. सिन्हा . अनुमति दी गई।

2. अपीलार्थी के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कवित अपराध के लिए कार्रवाई की गई है। प्रथम प्रतिवादी ने तृतीय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, हैदराबाद की अदालत में परिवाद दर्ज कराई। अपीलार्थी के दायित्व के संबंध से, जो पत्यावती प्रकृति का है. परिवाद याचिका के पैराग्राफ 2 में निम्नलिखित कथन दिया गया है जो निम्नानुसार हैः

> ‘‘2. यह कि अभियुक्त मैसर्स ऋषभ अल्फेम इंडिया लिमिटेड के नाम व स्टाइल से अपना व्यवसाय करने वाली कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 2 शातिनिवास अपार्टमेंट, मेटटुगुड़ा, सिकंदराबाद में है और पहली अभियुक्त कंपनी के प्रबंध निदेशक की क्षमता में अभियुक्त नंबर 2 द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है और अभियुक्त नंबर 3 से 6 कंपनी के निदेशक हैं। परिवादकर्ता फर्म से बातचीत के बाद सभी अभियुक्त परिवादकर्ता फर्म से वित्तीय सहायता लेने के लिए सहमत हुए थे। व्यापक

ऋण दस्तावेज निष्पादित करने के बाद उन्होंने परिवादकर्ता फर्म से 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता ली है। ऋण राशि लेते समय अभियुक्त व्यक्ति मूल राशि 10 लाख रुपये पर ब्याज देने पर भी सहमत हुए।"

3. अपीलार्थी का तर्क है कि प्रासंगिक समय पर, यह कंपनी का निदेशक नहीं था। अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर कि परिवाद याचिका में लगाए गए आरोपों के आधार पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 के प्रावधानों की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं, अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत हैदराबाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की और उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के आधार पर निम्नानुसार कहा:-

‘‘3. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि भले ही परिवाद में सभी आरोपों को सच मान लिया जाए, लेकिन वे वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाते हैं. चेक जारी करने से पहले. याचिकाकर्ता ने ए.। कंपनी के निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया, इसलिए, उसके खिलाफ कार्यवाही जारी

रखना अदालत की प्रक्रिया के दुरुप्रयोग के अलावा कुछ नहीं है और इसलिए उसने इसे रद्द करने की प्रार्थना की।"

4. परिवाद में आरोप यह है कि वर्तमान याचिकाकर्ता ए. कंपनी के निदेशकों में से एक है। केवल इसलिए कि वह एक निदेशक है, उस पर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि उसका मामला अधिनियम की धारा 141 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता। अधिनियम की धारा 141 के तहत, यह दिखाया जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के समय, कंपनी के व्यवसाय और दिन-प्रतिदिन के मामलों के संचालन के लिए जिम्मेदार है। आरोप है कि परिवादकर्ता फर्म के साथ बातचीत के बाद सभी अभियुक्त परिवादकर्ता से वित्तीय सहायता लेने के लिए सहमत हुए और व्यापक ऋण दस्तावेज निष्पादित करने के बाद, उन्होंने परिवादकर्ता फर्म से 10.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता ली है। चूंकि यह आरोप लगाया गया है कि सभी निदेशक-अभियुक्तों ने परिवादकर्ता फर्म से A.1 कंपनी द्वारा ली जाने वाली वित्तीय मदद के संबंध में बातचीत में भाग लिया था. यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सभी निदेशक A.1 कंपनी के दिन-प्रतिदिन के लेनदेन के लिए जिम्मेदार थे। इसलिए, परिवाद में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया

मामला बनाते हैं कि सभी निदेशक कंपनी के दिन प्रतिदिन के मामलों के प्रभारी और जिम्मेदार हैं।

5. दूसरा तर्क यह है कि चेक जारी करने के समय याचिकाकर्ता कंपनी का निदेशक नहीं था। यह तथ्य का प्रश्न है जिसे विचारण न्यायालय के समक्ष स्थापित किया जाना है। धारा 482 सीआर.पी.सी. के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथ्य का प्रश्न तय और निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, विवादित कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं है।"

4. यह विवाद में नहीं है कि किसी कंपनी के निदेशक के प्रत्यावर्ती दायित्व को दिखाने के लिए, परिवाद पर यह अभिवचन करना अनिवार्य है कि अभियुक्त कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था। परिवाद याचिका में ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है, हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में सही नहीं किया था। परिवाद याचिका में आरोप यह था कि सभी अभियुक्त निदेशकों ने अभियुक्त नंबर के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बातचीत में भाग लिया, जो हमारी राय में, इस निष्कर्ष को जन्म नहीं देगा कि अपीलार्थी कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों के लिए जिम्मेदार था। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत परिकल्पित अपराध में कई तत्व शामिल होते हैं जैसा कि इस न्यायालय की तीन न्यायाधीश पीठ

ने एस.एम.एस. फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला और अन्य [2005] 8 एससीसी 89 में निम्नलिखित शर्तों में माना है:-

"आवश्यक यह है कि जिन व्यक्तियों को धारा 141 के तहत आपराधिक रूप से उत्तरदायी बनाने की मांग की गई है, उन्हें अपराध के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी और जिम्मेदार होना चाहिए। कंपनी से जुड़ा हर व्यक्ति प्रावधान के दायरे में नहीं आएगा। केवल ये व्यक्ति ही आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे जो किसी अपराध के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के प्रभारी और जिम्मेदार थे। इससे यह पता चलता है कि यदि किसी कंपनी का कोई निदेशक, जो प्रासंगिक समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी नहीं था और जिम्मेदार नहीं था. प्रावधान के तहत उत्तरदायी नहीं होगा। दायित्व प्रासंगिक समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के प्रभारी और जिम्मेदार होने से उत्पन्न होता है, न कि किसी कंपनी में केवल एक पदनाम या कार्यालय रखने के आधार पर। इसके विपरीत, किसी कंपनी में कोई पद या पद न रखने वाला व्यक्ति उत्तरदायी हो सकता है यदि वह प्रासंगिक समय पर किसी कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार होने की मुख्य आवश्यकता को पूरा करता है। दायित्व किसी कंपनी के मामलों में व्यक्ति की भूमिका

पर निर्भर करता है, पदनाम या स्थिति पर नहीं। यदि निदेशक या प्रबंधक या सचिव होना आपराधिक दायित्व डालने के लिए पर्याप्त था, तो अनुभाग ने ऐसा कहा होगा। "प्रत्येक व्यक्ति" के बजाय अनुभाग में कहा गया होता "किसी कंपनी में प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक या सचिव उत्तरदायी है"…. आदि। विधायिका को पता है कि यह आपराधिक दायित्व का मामला है जिसका मतलब है कि जहां तक उस व्यक्ति को उत्तरदायी बनाने की मांग है तो गंभीर परिणाम होंगे। इसलिए.. केवल उन्हीं व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये प्रासंगिक समय पर अपराध से जुड़े थे।"

5. कंपनी की ओर से उसके निदेशकों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बातचीत. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध गठित करने के उद्देश्य से एक घटक नहीं है। इसके अलावा, एक व्यक्ति की ओर से एक प्रत्यावर्ती दावित्य का अनुरोध किया जाना चाहिए और उसे साबित किया जाना चाहिए। यह केवल अनुमान का विषय नहीं हो सकता है।

6. सबिता राममूर्ति और अन्य बनाम आर. एस. एस. चन्नबसवराध्या, में, [2006] 10 एससीसी 581 में रिपोर्ट किया गया. इस न्यायालय ने राय दी:-

“7. परिवाद याचिकाओं के अवलोकन से पता चलता है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 में निहित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था। यह सच हो सकता है कि परिवादकर्ता के लिए धारा के शब्दों को विशेष रूप से पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो आवश्यक है वह तथ्य का स्पष्ट विवरण है ताकि अदालत को प्रथम दृष्टया राय पर पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके कि अभियुक्त अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। धारा 141 एक कानूनी कल्पना कोउठाती है। उक्त प्रावधान के कारण, हालांकि एक व्यक्ति इस तरह के अपराध के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है, लेकिन वह इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होगा। जहां तक कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत या निगमित कंपनी का संबंध है. इस तरह के प्रत्यावर्ती दायित्व का अनुमान केवल तभी लगाया जा सकता है, जब अपेक्षित कथन, जिनका उल्लेख किया जाना परिवाद याचिका में आवश्यक है, बनाये जाएं, ताकि अभियुक्त को कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया जा सके। इससे पहले कि एक व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया जा सके, वैधानिक आवश्यकताओं के कड़ाई से अनुपालन पर जोर दिया जाएगा। न केवल परिवाद याचिकाओं के पैरा 7 में दिए गए कथन उक्त वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा

नहीं करते हैं. यहां प्रतिवादी के बेटे द्वारा दिए गए गवाह के शपथ बयान में कोई भी बयान शामिल नहीं है कि अपीलार्थी कंपनी व्यवसाय के प्रभारी थे। ऐसे मामले में जहां अदालत को समन जारी करने की आवश्यकता होती है जिससे अभियुक्त को किसी प्रकार का उत्पीडन हो सकता है, अदालत को वैधानिक आवश्यकताओं के कड़ाई से अनुपालन पर जोर देना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अनुसार परिवादकर्ता शपथ पर बयान देने के लिए बाध्य है कि अपराध कैसे किया गया है और अभियुक्त व्यक्ति इसके लिए कैसे जिम्मेदार हैं। ऐसी स्थिति में, अंततः, अभियोजन तुच्छ या अन्यथा दुर्भावनापूर्ण पाया जाता है, न्यायालय परिवादकर्ता के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन के लिए मामला दर्ज करने का निर्देश दे सकता है। अभियुक्त हर्जाने के लिए मुकदमा दायर करने का भी हकदार होगा। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों को उपरोक्त दृष्टिकोण से समझा जाना आवश्यक है। "

(यह भी देखे एवरेस्ट एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड बनाम राज्य सरकार, दिल्ली एन. सी. टी. और अन्य, जे. टी. (2007) 5 एस. सी. 529 में रिपोर्ट किया गया और रघु लक्ष्मीनारायणन बनाम एम / एस फाइन्स ट्यूब. जे. टी. (2007) 5 एस. सी. 552 में रिपोर्ट किया गया।

7. उपर्युक्त कारणों से आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार इसे रद्द किया जाता है। संज्ञान लेने का आदेश निरस्त किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है.

कोई लागत नहीं.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कमला बाँयला (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।